भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 454

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेलंगाना में औद्योगिक गलियारे

454. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हैदराबाद-नागपुर और हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारों के लिए तेलंगाना से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ज़हीराबाद एनआईएमजेड और हैदराबाद के निकट एक नोड को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में मान्यता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रारंभिक डिज़ाइन रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद हैदराबाद-वारंगल नोड के लिए वित्तपोषण को मंजूरी देगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गलियारा परियोजनाओं के वित्तपोषण समर्थन और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): तेलंगाना सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर (एचएनआईसी) के भाग के रूप में जहीराबाद नोड के विकास के लिए अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक कॉरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी) के भाग के रूप में, हैदराबाद फार्मा सिटी को शुरुआत में तेलंगाना राज्य में विकास के लिए चिन्हित किया गया था। चूंकि राज्य सरकार परियोजना की पुष्टि करने में असफल रही, अतः एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड ने 8 जून 2022 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना को बंद करने का निर्णय किया।

जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र (जेडआईए) को एचएनआईसी कॉरिडोर के तहत प्राथमिक नोड के रूप में चिन्हित किया गया है।

इसके अलावा, तेलंगाना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर, विभाग ने (i) तेलंगाना के संगारेड्डी जिले (पूर्ववर्ती में मेडक) (22 जनवरी 2016 को) और (ii) तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद फार्मा सिटी एनआईएमजेड (10 दिसंबर 2019 को) में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया।

संगारेड्डी जिले में अवस्थित एचएनआईसी नोड के तहत परियोजना के पास 2,360 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 3,245 एकड़ का एक्टिवेशन क्षेत्र है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से भारत सरकार के अंश का हिस्सा, इक्विटी के रूप में 596 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 655 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए "एनआईसीडीआईटी जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी लिमिटेड" नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) निगमित किया गया है और नए शहरों के लिए परियोजना प्रबंधन (पीएमएनसी) के चयन के लिए निविदा कार्य शुरू कर दिया है।

*****